

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)**पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 011/2020 (GCMS 2020/00024)	दायर दिनांक 05.06.2020	निर्णय दिनांक 18.02.2021
--	---------------------------	-----------------------------

अनवान

मथरालाल पिता मोहनलाल जाति नट उम्र वयस्क निवासी
मनकेसर तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़

अपीलान्ट**बनाम**

श्री सरकार जरिए तहसीलदार बेंगू तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़।

रेस्पोंडेंट

**--:: अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय तहसीलदार बेंगू बमिसल
क्रमांक 1/2020 निर्णय एवं आदेश दिनांक 20.05.2020 ::--**

उपस्थिति :- श्री छोगालाल जाट
श्री भेरुलाल सालवी

अधिवक्ता अपीलांट
राजकीय अधिवक्ता

--:: निर्णय ::--

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत एक अपील विरुद्ध रेस्पोंडेंट के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय आदेश न्याय, नियम एवं वाक्याति तथ्यों के विपरित होकर निरस्त किए जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का रायती ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलांट अतिक्रमी ने मौजा तुरकड़ी की आराजी नम्बर 410 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म तलाई पर सम्वत् 2077 में अनाधिकृत कब्जा कर पत्थर डालकर एवं कोट कर अतिक्रमण कर लिया है, जिस पर विचारण न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को जरिए सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में अपीलांट दिनांक 20.05.2020 को उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया फिर भी विचारण न्यायालय ने सुनवाई का समुचित अवसर दिए बगैर बेदखल किए जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किए जाने योग्य है। विवादित आराजीयात में सम्वत् 2008 में किस्म तलाई अंकित थी परन्तु मौके पर कोई तलाई नहीं होकर आबादी हल्के से लगी हुई भूमि



है, फिर भी विचारण न्यायालय ने तलाई की भूमि मानते हुए बेदखल किए जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलांट जाति से नट होकर गरीब तबके का व्यक्ति है जिसका मौजा तुरकड़ी में कोई आवासीय मकान नहीं होने व उक्त भूमि आबादी से लगी हुई होने से पत्थर की कोट कर चढ़र डालकर अस्थाई निवास बनाया है व नट जाति के व्यक्ति स्थाई निवास नहीं करते हुए गांव-गांव में घूमकर नृत्य करते रहते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांट घुमक्कड़ जाति का व्यक्ति है जो कभी भी स्थाई निवास नहीं करेगा फिर भी विचारण न्यायालय ने अतिक्रमण होना मानते हुए बेदखल किए जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किए जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं प्रदान करते हुए जल्दबाजी में निर्णय पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश विवादित आराजीयात व पक्षकारान श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में अवस्थित होने से अपील अपीलांट न्यायालय आप में पेश हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील पेश है। अन्य उजरात वक्त बहरा अर्ज किए जाएंगे, अंत में अपीलांट की और से प्रार्थना की गई कि अपील अपीलांट स्वीकार पर भी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व आदेश दिनांक 20.05.2020 निरस्त फरमाया जावें।

इस पर अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस के तलब किया गया। रेस्पोंडेंट की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर तहसीलदार बेंगू के पत्रांक/राजस्व-बी/2020/01 दिनांक 12.10.2020 से उनकी मूल पत्रावली संख्या 001/2020 अनवानी सरकार बनाम मथुरालाल पिता मोहनलाल जाति नट निवासी मनकेसर तहसील बेंगू अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता है। अपील अपीलांट अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है।

दिनांक 18.02.2021 को प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रकरण में सीधे बहस के निवेदन किया गया इस पर उभयपक्ष की सहमति से प्रकरण में सीधे बहस पत्रावली की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का रायती ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलांट अतिक्रमी ने मौजा तुरकड़ी की आराजी नम्बर 410 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म तलाई पर सम्वत् 2077 में अनाधिकृत कब्जा कर पत्थर डालकर एवं कोट कर अतिक्रमण कर लिया है, जिस पर विचारण न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को जरिए सम्मन नोटिस तलब किया गया। अपीलांट दिनांक 20.05.2020 को उपस्थित होकर



जवाब नोटिस प्रस्तुत किया फिर भी विचारण न्यायालय ने सुनवाई का समुचित अवसर दिए बगैर बेदखल किए जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किए जाने योग्य है। विवादित आराजीयात में सम्वत् 2008 में किस्म तलाई अंकित थी परन्तु मौके पर कोई तलाई नहीं होकर आबादी हल्के से लगी हुई भूमि है, फिर भी विचारण न्यायालय ने तलाई की भूमि मानते हुए बेदखल किए जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किए जाने योग्य है। इसके जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तलाई दर्ज रेकार्ड होकर राजकीय भूमि की श्रेणी में आती है जिससे उक्त विवादित भूमि नियमन की पात्रता नहीं रखती है, इसके साथ ही विवादित आराजीयात की किस्म तलाई होने से प्रतिबंधित की श्रेणी में आती है जिससे भी विवादित आराजीयात नियमन की श्रेणी में नहीं आती है, जिससे अपीलांट की अपील सारहीन होकर खारीज किये जाने योग्य है। प्रचलित नियमों के अनुसार विवादित भूमि का आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। राजकीय भूमि अतिक्रमण पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। अतः योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बेंगू के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस समाप्त की। बहस के रिक्टल में विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया अपीलांट जाति से नट होकर गरीब तबके का व्यक्ति है जिसका मौजा तुरकड़ी में कोई आवासीय मकान नहीं होने व उक्त भूमि आबादी से लगी हुई होने से पत्थर की कोट कर चदर डालकर अस्थाई निवास बनाया है व नट जाति के व्यक्ति स्थाई निवास नहीं करते हुए गांव-गांव में घूमकर नृत्य करते रहते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांट घुमक्कड़ जाति का व्यक्ति है जो कभी भी स्थाई निवास नहीं करेगा फिर भी विचारण न्यायालय ने अतिक्रमण होना मानते हुए बेदखल किए जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किए जाने योग्य है। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस पत्रावली समाप्त की। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। हमने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का अवलोकन किया। अधिनियम में धारा 91 के तहत व्यवस्था की गई है कि :-

91 Unauthorised occupation of Land - (1) Any person who occupies or continues to occupy any land without lawful monthly shall be regarded as a trespasser and may be summarily evicted there from by the Tehsildar at any time of his motion or upon the application of a local authority at whose disposal such land has been placed, and 69[any crop standing, or any} building or other construction erected. or anything deposited on such land shall, if not



removed with in such reasonable time as the Tehsildar may from time to time fix for the purpose, be liable to be forfeited to the State and to be disposed of 1[in the case of any such crop, in the manner he thinks fit and in other cases] as the Collector may direct:

Provided that the Tehsildar may in lieu of ordering the forfeiture of any such building or other construction, order the demolition of the whole or any part thereof.

1[(2) Such trespasser shall further be liable to pay, for 'each agricultural year during the whole or any part where of has been in such unauthorized occupation of the land, a penalty which may extend to fifty times the annual rent, or assessment, as the case may be, for the first act of trespass. In the case of each subsequent ad of trespass, he shall by the order of Tehsildar, be liable to commitment to civic person for a term which may extend to three months and to pay penalty to the extent as aforesaid. The amount of such penalty shall be recovered as an arrear of land revenue, and]

1[(3) Where the trespasser ordered to be committed to civil prison under subsection (2) satisfies the Tehsildar by whom he is ordered to be committed to civil prison that he intends to present an appeal, the Tehsildar shall order that such trespasser be released on his own bond for such periods will afford him sufficient time present the appeal and obtain stay order from the Appellate Court and such order shall so long as he is so released on bond be deemed to be suspended]

(4) In any of the following cases, namely.-

(i) where the trespasser does neither vacate the land not make appearance in response to the notice issue under sub-section (3), or

(ii) where in response to such notice, the trespasser does not vacate the land and makes appearance but-

(a) does not show any such cause, or

(b) makes any representation which is rejected after such inquiry and hearing as may be necessary in the circumstances of the case, the Tehsildar shall, unless, in the case covered by clause (ii) the trespasser under-takes to vacate the land within a week's time- and vacates it whine such time order the removal of the trespasser from such land and shall remove or depute any person, to remove him therefrom and take possession thereof; and if the Tehsildar or the person so deputed is opposed or !impeded in taking possession of such land, the Tehsildar shall apply to a Magistrate having jurisdiction and such Magistrate shall enforce the surrender of the land to the Tehsildar.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Tehsildar may, in case any such land belongs to the category specified in clause (ii) of the proviso to Section 97, sell it, with the approval of the Sub-Divisional Officer, to the trespasser upon payment by him of the premium therefor at the rate fixed under Section 96 and applicable to such land in addition to the assessment and penalty recoverable from him under sub-section (2) in respect of the whole period of unlawful occupation

1[(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) - (a) whoever occupies any land without lawful authority or, having occupied such land before coming into force of the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Act, 1992, fails to remove such occupation within fifteen days from the date of service of a notice in writing calling upon him to do so by the Tehsildar shall, on conviction, be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to three years and with fine which may extend to twenty thousand rupees; and

(b) whoever, being an employee of the State Government specifically entrusted by an order of the Collector in writing with the duty to stop or prevent an offence punishable under this sub-section wilfully or knowingly neglects or deliberately omits to stop or prevent such offence, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees or with both :



Provided that, in the case of an offence under clause (a), the court may for any adequate or special reason to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than one month :

Provided also that no investigation of an offence under clause (a) of this sub section shall be made by an officer below the rank of a Deputy Superintendent of Police :

Provided further that no court shall take cognizance of an offence under clause (b) except with the previous sanction of the Collector.

विवादित भूमि राजकीय भूमि दर्ज होने से पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार बेंगू ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करके बेदखली, शास्ति आरोपण किया गया। इसके साथ ही अपीलांत स्वयं द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण करना स्वीकार किया गया है। राजकीय भूमि अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। इसके साथ ही पत्रावली पर अपीलांत द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे अपीलांत का विवादित आराजीयात पर किसी भी प्रकार को कोई हक-हकूक निहित है। अपीलांत्स द्वारा अतिक्रमण किया गया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.05.2020 द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक निर्णय पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.05.2020 विधि सम्मत होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन एवं हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.05.2020 संपुष्ट किये जाने योग्य प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में हमें योग्य अधीनस्थ तहसीलदार, बेंगू के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलांत खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रकरण राजस्व अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज की जाती है, एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बेंगू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.05.2020 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 18.02.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

